डाक्टरों में भी रचनाकार एवं कलाकार बसते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय ईएसआईसी मैडिकल कॉलेज के तीन दिवसीय उत्सव में डाक्टरी पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने यह हाइलाइट किया कि डाक्टरी की पढ़ाई, जिसे काफी कठिन समझा जाता है भी पढ़ने वाले के भीतर मौजूद कवि, गायक, एक्टर आदि-आदि को मार नहीं सकती। पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने साथ-साथ इन बच्चों ने इस अवसर पर अपने विभिन्न कलात्मक पहलुओं का प्रदर्शन भी पूरी महारत के साथ किया।

रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से भी छात्र-छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा एवं अभिव्यक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया। अधिकांश रंगोली पुलवामा के आंतकी हमले व देशभक्ति के साथ-साथ शान्ति का संदेश दे रही थी। आज एक ओर जहां कुछ वर्ग विशेष के लोग एवं धर्म विशेष के लोगों को आंतकवाद के लिये जिम्मेदार ठहराने का दुष्प्रचार

छुपारुस्तम : डिप्टी डायरेक्टर दिनेश कुमार निर्वाण

कर रहे हैं, वहीं इन बच्चों की दो रंगोली बता रही थीं कि आंतकियों का कोई धर्म नहीं होता, सभी देशवासियों को मिलकर इससे निपटना चाहिये।

वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी बच्चों ने समाज के प्रति अपनी जागरूकता का अच्छा परिचय दिया।

मर्द को भी दर्द होता है, कोई सुनने वाला नहीं

फिल्मी डायलॉग 'मर्द को दर्द नहीं होता' के विपरीत 'मर्द को भी दर्द होता है' शीर्षक से बना एक स्किट ईसआईसी मैडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुत किया। दिनांक 24 से 26 जनवरी तक मैडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्सव के आखिरी दिन म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम में सांयकाल एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यूं तो सभी प्रस्तुतियां बेहतरीन थी, लेकिन उक्त स्क्रिप्ट अपने आप में एक बड़ा संदेश दे गयी। इनमें दर्शाया गया कि कैसे घर-परिवार में ही छोटे से लेकर बड़े लड़कों के साथ यौनाचार होता रहता है और वह इस कदर डरा-सहमा रहता है कि अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं पाता। स्किट में बताया गया कि महिलाओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर है, बच्चों के लिए है, रेप व छेड़खानी के विरुद्ध कानून है, परन्तु मर्दों के लिए न ही कोई हेल्पलाइन है न तो कोई कानून उन्हें यौनाचार से संरक्षण प्रदान करता है।

स्किट में आईपीसी की धारा 375 के रद्द किये जाने का जिक्र करते हुए 'मी टू' का भी उल्लेख किया गया। यानी जिस प्रकार महिलाओं ने 'मी टू' नामक हथियार का इस्तेमाल किया है उसी तरह मर्दों के लिए भी यह हथियार कारगर होना चाहिए। मजे की बात तो यह थी कि स्किट प्रस्तुत करने वाले कलाकारों में छात्रायें अधिक थीं।

विषय था डाक्टरों द्वारा ली जाने वाली शपथ (हिपोक्रेटिक ओथ)। कुछ बच्चे इसके समर्थन में तो कुछ इसके विरुद्ध बोले। विदित है कि इस शपथ के द्वारा डाक्टरों को अपने मरीजों के अच्छे माननीय व्यवहार तथा ईमानदारी से उनका इलाज करने के लिये बांधा जाता है। कुछ वक्ता इस बंधन को आज भी जरूरी मान रहे थे तो कुछ इसे एकदम पांखड बता रहे थे। एक वक्ता का तर्क था कि आज जब डाक्टरों को अदालत के माध्यम से ही मरीजों से निपटना है तो इस शपथ का क्या औचित्य रह गया है। एक अन्य वक्ता ने तर्क दिया कि शपथ खाने का कोई औचित्य इसलिये भी नहीं रह जाता कि शपथ तोड़ने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। देश के नेता पदभार संभालते समय आये दिन झूठी शपथ खाते हैं। शपथ के द्वारा किये गये वायदों पर कभी कायम नहीं रहते तो डाक्टरों की शपथ में क्या बचता है।

एक वक्ता ने यह भी कहा कि चिकित्सा व्यवसाय की आज इस कदर दुर्दशा हो चुकी है कि कोई डाक्टर चाहते हुए भी अपनी शपथ एवं इच्छा के अनुसार अपने मरीजों को सेवाएं नहीं दे सकता। उसने बीके अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोई भी डाक्टर कैसे अपनी शपथ के अनुसार मरीजों को सेवायें दे सकता

बच्चों ने पढ़ाई में आने वाली कठिनाई वर्णन भी बड़े हास्य-विनोद एवं व्यंग्यात्मक ढंग से किया

डाक्टरी की पढ़ाई कठिनतम पढ़ाईयों में से एक मानी गयी है। इसके लिये कड़ी प्रवेश परीक्षा द्वारा योग्यतम विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बावजूद भी इसे पढ़ने वालों को आने वाली कठिनाईयों का वर्णन 2017 बैच के छात्र गणेश शर्मा ने बड़े ही रोचक ढंग से अपनी कवितानुमी तुकबंदी के द्वारा पेश किया। इसका शीर्षक था 'प्रोफेसर पढ़ाता नहीं वायवा में कहता है तुझे कुछ आता नहीं'। हर विषय की पढ़ाई के बाद जब वह शीर्षक....वायवा में कहता है तुझे कुछ आता नहीं' बोलने का वक्त आता तो वह माइक श्रोताओं की ओर कर देता और तमाम छात्र-छात्रायें पूरे जोर से उस जुमले को पूरा करते हुए अपने आप को जोड़ लेते इससे माहौल तो जीवंत होता ही था साथ में समस्याओं को साझा करने का संदेश भी मिलता था।

है? जाहिर है वक्ता का इशारा 'एक अनार सौ बीमार' की ओर था। सभी जानते हैं कि एक बीके क्या किसी भी सरकारी अस्पताल में न तो पर्याप्त डाक्टर व अन्य स्टाफ है और न ही आवश्यक उपकरण व दवायें आदि। और तो और कुत्ता काटे के (रैबीज) इन्जैक्शन तक इन अस्पतालों में नहीं रहते। ऐसी शपथ क्या अपनी ऐसी-तैसी करायेगी?

यद्यपि एक महत्वपूर्ण बात जो वक्ताओं ने मंच से तो नहीं कही लेकिन इस संवाददाता से व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि प्राईवेट मैडिकल कॉलेज से डाक्टर बनने के लिये लाखों-करोड़ों की डोनेशन व फीस भरने व जवानी के दस साल लगाने के बाद डाक्टर को मिलने वाले एक डेढ़ लाख के वेतन से तो लागत का ब्याज भी नहीं निकलता। प्राईवेट कॉलेज ही क्यों सरकारी कॉलेज कौन से अब सस्ते रह गये हैं? इनमें पढ़ाई पूरी करने में भी बहुत अधिक खर्चा आने लगा है। ऐसे में भला कोई डाक्टर कैसे और कब तक शपथ से बंधा रह पायेगा? वह हर जायज-नाजायज तरीके से, शीघ्रातिशीघ्र अपनी लागत निकालना चाहेगा।

ऑडिटोरियम में बनाई गयी ध्वनि व्यवस्था को ध्वनि प्रदूषण व्यवस्था कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। ऑडिटोरियम के अन्दर ध्वनि इतनी ऊंची थी कि बाहर सड़क पर भी साफ सुनाई दे रही थी। कायदे से ध्वनि हॉल के बाहर तो जानी ही नहीं चाहिये और भीतर भी एक सुहावनी एवं तयशुदा ऊंचाई पर ही रहनी चाहिये। यह अगर अनपढ़ जाहिलों द्वारा किया जाता तो बात समझ में आती परन्तु यह सब शहर के उच्चतम एवं वरिष्ठतम चिकित्सा वैज्ञानिकों की मौजूदगी में लगातार 4 घंटे तक होते रहना समझ से परे है।

शहीद की सुहागन

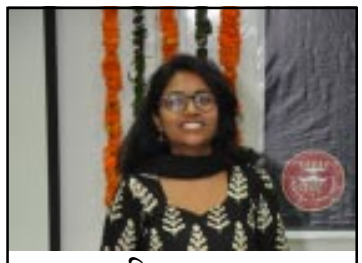

कविता / पूजा

है वो वजूद में ही शामिल,
ये बात कोई खास नहीं है।
हाँ ये बात अलग है मगर कि
अब वो मेरे पास नहीं है।

कल की ही बात है, वक्त-ए-रुखसत
अपने हाथों से मेरा सिंदूर लगाया था,
चाहे कुछ भी हो जाये, हर एक हाल में
लौट के आऊँगा ये मुझको बताया था।

तुमने जो कहा था, मेरा इंतजार करना,
मैंने आंखों को देख पूरा रास्ता कर लिया
आखिरी आलिंगन ने जैसे गुदगुदाया था,
अब गुदगुदी को जीने का वास्ता कर लिया।

याद तो किया होगा, मुझको भी यकीनन,
जब उड़ते परखच्चे तिरंगे को लाल किया होगा
तुझे हवा में लीव होते देखकर बेशक,
सर-ए-जमीन-ए-कश्मीर ने कोलाहल किया होगा।

मेरा फौजी मेरा सरताज मगर
वादे का पक्का निकला
लौट के आखिर मिलने आया
हर वहम कच्चा निकला

आंखे हैं अश्कों का समदंर, पर रोने की प्यास नहीं है।
उस ताबूत से लिपट क्या रोना, जिसमें लाश नहीं है।
है वो वजूद में ही शामिल, ये बात कोई खास नहीं है।
हां ये बात अलग है मगर कि वो अब वो मेरे पास नहीं है।

ईएसआई मजदूरों के वेतन से 6½ प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत वसूलेगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) ईएसआई कार्पोरेशन मजदूरों के वेतन से पौने दो प्रतिशत व मालिकान से पौने पांच प्रतिशत के हिसाब से जो कुल साढ़े छह प्रतिशत वसूलती थी अब उसे घटा दिया गया है। अब मजदूरों के वेतन से एक प्रतिशत और मालिकान से चार प्रतिशत ही लिया जायेगा। जाहिर है इससे मजदूरों व कारखानेदारों को थोड़ी आर्थिक राहत जरूर मिलेगी, परन्तु इस राहत की बजाये यदि ईसआईसी अपनी सेवाओं खासकर चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक सुधार करके मजदूरों को राहत देती तो कहीं ज्यादा उपयोगी होता।

मजदूरों के करीब एक लाख करोड़ रुपयों के ढेर पर कुंडली मारे बैठा ईएसआई निगम स्थानीय मैडिकल कॉलेज अस्पताल में आवश्यक स्टाफ तक भर्ती नहीं कर रहा है। यहां 102 क्लर्कों की जगह मात्र 25 क्लर्क हैं। इसके चलते 2 से 3 लाख वेतन पाने वाले वरिष्ठ डाक्टर अपना काम छोड़कर 30-40 हजार वेतन पाने वाले क्लर्क का काम करने को मजबूर है। इसी तरह लेबोरेट्री में जहां 68 टेक्नीशियनों की जरूरत है और ये पद स्वीकृत भी हैं लेकिन भर्ती किये गये हैं मात्र 4 जबकि 16 ठेकेदारी व्यवस्था में चल रहे हैं। ऑपरेशन थियेटर में सर्जन डाक्टरों की सहायता के लिए 48 टेक्नीशियनों के पद स्वीकृत हैं जिनके स्थान पर मात्र 4 ही भर्ती किये गये हैं, 16 ठेकेदारी पर हैं। जब 48 की जगह 20 ही टेक्नीशियन ऑपरेशन थियेटरों में होगे तो डाक्टर बेचारे कितने ऑपरेशन कर लेंगे? रेडियोलॉजी यानी एक्स-रे व अल्ट्रासाऊंड विभाग में रेडियोग्राफर व टेक्नीशियन आदि के 23 पद स्वीकृत हैं। इसके स्थान पर कुल 12 लोगों से काम चलाया जा रहा है, इनमें से भी केवल 10 नियमित व 2 ठेके पर हैं।

ईएसआई हैल्थ केयर के लिए अब राज्य सरकारों को आठवां हिस्सा नहीं देना होगा

विदित है कि प्रत्येक राज्य की भांति हरियाणा में ईएसआई की स्वास्थ्य सेवायें चलाने का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा हुआ है। इसके लिये राज्य सरकारें कुल बजट का मात्र आठवां हिस्सा (करीब 12 प्रतिशत) राज्य सरकार और शेष ईएसआईसी वहन करती है। परन्तु अब कार्पोरेशन ने यह शर्त भी हटा दी है। यानी शत प्रतिशत खर्चा ईएसआई कार्पोरेशन वहन करेगा।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि हरियाणा सरकार ने अपने करीब 30 लाख ईएसआई कवर्ड मजदूरों को स्वास्थ्य सेवायें देने के लिए मात्र 172 करोड़ का बजट बनाया है जो बीते वर्ष 162 करोड़ का था और उसमें से भी केवल 148 करोड़ ही खर्च किया गया था। ईएसआईसी के नियमानुसार प्रति श्रमिक 3000 रुपये वार्षिक के हिसाब से 30 लाख श्रमिकों के लिये 900 करोड़ तक का बजट बनाया जा सकता है। अपने इन श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार यदि 900 करोड़ का बजट बनाती तो इसे मात्र 112 करोड़ ही खर्च करने पड़ते। लेकिन संघियों की यह मजदूर विरोधी सरकार भी अपने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह 100 करोड़ बचाने के लिऐ ईएसआईसी से मिलने वाले 800 करोड़ छोड़ देती है।

ईएसआईसी के नये नियमानुसार अब राज्य सरकार को आठवां भाग भी नहीं देना पड़ेगा तो 900 करोड़ के बजट का पूरा खर्च ईएसआईसी वहन करेगी। इतना ही नहीं अब 3000 प्रति श्रमिक प्रति वर्ष की शर्त भी हटा ली गयी है। अब देखना है कि खट्टर सरकार व इसके निकम्मे अधिकारी कितना बजट बनाते हैं और कैसी स्वास्थ्य सेवायें अपने 30 लाख श्रमिकों को प्रदान करते हैं।

600 बैड के इस अस्पताल के लिए नर्सिंग स्टाफ संख्या जहां 500 होनी चाहिये वहां स्वीकृत पद मात्र 203 हैं। इस मुख्यालय में बैठे मजदूर विरोधी अफसरों का तर्क है कि एमसीआई मानक के अनुसार 203 पद ही बनते हैं। दूसरी ओर ईएसआई की अपनी किताब में इतने बड़े अस्पताल के लिये 500 पद लिखे हैं। उन मूर्ख अधिकारियों से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि क्या एमसीआई ने मना किया है कि 203 से अधिक नर्सिंग स्टाफनहीं रखा जायेगा? दरअसल एमसीआई कोई सेवा देने वाला संस्थान नहीं है, यह तो केवल न्यूनतम मानक तय करने वाला संस्थान है जबकि ईएसआई सेवा देने वाला संस्थान है जिसके लिए वह अपने मरीजों से अग्रिम वसूली करता है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि 203 पद भी पूरे भरे नहीं हैं, केवल 140, जिनमें 80 ठेकेदारी पर हैं, से ही काम को घसीटा जा रहा है। नर्सिंग अर्दली (वार्ड बॉय) के 257 पद स्वीकृत हैं, जिनके स्थान पर 90 नियमित व 50 ठेके पर हैं।

जाहिर है इन सब कमियों का दुष्प्रभाव चिकित्सा सेवाओं पर पड़ना लाजमी है। इन हालात में बढ़िया से बढ़िया डाक्टर भी अपनी सर्वोत्तम सेवायें नहीं दे पा रहा है। ऐसे माहौल में वरिष्ठ डाक्टर जो काम करना भी पसंद नहीं करते, अव्वल तो वे यहां आते नहीं, आ भी जाते हैं तो शीघ्र ही छोड़ जाते हैं।